(घ) क्या खान से निकाले गये कोयले की मात्रा सूचित की गई मात्रा के अनुरूप नहीं है तथा श्रमिकों की संख्या और उनको भुगतान की गई राशि लेखा प्रस्तावों में दिखाई गई राशि से नहीं मिलती है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध शिकायतें

1349. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के तिवारी मंत्रिमंडल के विरुद्ध विरोधी दलों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन में मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन मंत्रियों और मुख्य-मंत्री के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : उत्तर प्रदेश के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित राष्ट्रपति को सम्बोधित दिनांक 15 अप्रैल, 1977 का एक ज्ञापन, जिस पर राज्य के 19 विधायकों ने हस्ताक्षर किये थे, तथ्यों का पता लगाये जाने के लिए सामान्य कार्यविधि के अनुसार राज्यपाल को भेज दिया गया है । उक्त ज्ञापन में लगाये गए आरोपों का स्वरूप अथवा उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, इस स्टेज पर प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास धनराशि का अपव्यय

1350. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अपने मूल उद्देश्य की उपेक्षा की और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं तथा युवा कांग्रेस नेता श्री संजय गांधी की स्वार्थसिद्धि में धनराशि का अपव्यय किया ;

(ख) क्या सरकार ने निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) जी, नहीं । माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर है ।

(ख) प्राप्त हुई कुछ शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sub-leasing of land by D.S.I.D.C.

1351. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a proposal has been sent to the Central Government to allow the Delhi State Industrial Development Corporation (DSIDC) to sub-lease the land utilised for construction of the sheds;